बुलन्द उत्तर प्रदेश की बुलन्द तस्वीर बुन्देलखण्ड

दुर्गम रास्ते, प्यास बुझाने को पानी की किल्लत, औद्योगिक शून्यता आदि... बुन्देलखण्ड की यह तस्वीर मार्च 2017 से पहले की थी। बुन्देलखण्ड के विकास को योगी सरकार ने प्राथमिकता में रखा। बुन्देलखण्ड में डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण युद्धस्तर पर हो रहा है। केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन एवं राज्य सरकार के क्रियान्वयन से बुन्देलखण्ड में 'हर-घर-जल' योजना साकार होने जा रही है जिससे लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की धरती बुन्देलखण्ड आज तरक्की के पथ पर अग्रसर है।

"भारत रक्षा क्षेत्र का बड़ा हब बनेगा। 'मेक इन इंडिया' के सपने को साकार करने वाले डिफेंस कॉरिडोर में युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा साथ ही भारत रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ ही निर्यातक भी बनेगा। दुनिया के बड़े हिस्से में मानवता की रक्षा का जिम्मा भारत का ही है।"

(डिफेंस एक्सपो, लखनऊ के उद्घाटन अवसर पर)

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

रक्षा क्षेत्र का नया मैन्युफैक्चरिंग हब

आत्मनिर्भरता

रमेश वर्मा

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बुन्देलखण्ड के तकदीर की लकीर माना जा रहा है। वर्ष 2018 में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस कॉरिडोर की घोषणा की थी। यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। बीते दिनों बंगलुरू में हुए एयरो इंडिया शो-2021 में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु 4,500 करोड़ रुपये के 17 नए एमओयू प्रस्ताव राज्य सरकार को मिले थे। इसमें रक्षा आयुध निर्माण व बैलिस्टिक सामग्री निर्माण के लिए एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड का 2,400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव अहम है।

लॉकडाउन के दौरान यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना तमाम बाधाओं से अप्रभावित रही। वहीं सबसे खास बात यह है कि इस अवधि में भी डिफेंस एंड एयरो स्पेस नीति से सम्बन्धित गाइडलाइन तैयार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा 200 से ज्यादा देशी-विदेशी कम्पनियों के साथ पत्र व्यवहार कर डिफेंस एंड एयरोस्पेस पॉलिसी के बारे में बताया गया। अब तक 4 नोड्स में 1,377 हेक्टेयर से अधिक जमीन क्रय की जा चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा झांसी नोड में 1,030 हेक्टेयर जमीन क्रय की गई है। शुरुआत में 23 कम्पनियों से एमओयू किया गया था। लॉकडाउन के दौरान पांच कम्पनियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने एमओयू साइन किया है। झांसी नोड उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का सबसे बड़ा नोड है। इस नोड में कम्पनियों द्वारा किये गये अनुबन्ध आयुध निर्माण, बख्तरबंद गाड़ियों के आधुनिकीकरण एवं मल्टीबैरल ग्रनेड लान्चर से सम्बन्धित हैं। साथ ही एक सेंटर ऑफ एक्सीलैंस की स्थापना प्रस्तावित है। भविष्य में यहां पर गोला-बारूद टेस्टिंग फैसिलिटी भी लगाने की योजना है। विनिर्माण उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की ओर से निवेशकों को विभिन्न सुविधाएं जैसे जमीन की खरीद पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

1030 हेक्टेयर भूमि झांसी जनपद में क्रय की गई

102 हेक्टेयर भूमि चित्रकूट जनपद में चिन्हित

99 हेक्टेयर भूमि चित्रकूट जनपद में क्रय की गई

"उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में 06 नोड आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी तथा चित्रकूट हैं। प्रदेश सरकार ने हर नोड के लिए पर्याप्त लैण्डबैंक की व्यवस्था की है। फरवरी, 2019 में प्रधानमंत्री जी द्वारा झांसी नोड का शुभारम्भ किया गया।"

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

विकास को मिली रफ्तार

बजट 2021-22

वीरभूमि बुन्देलखण्ड को उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में कई उपहार दिये हैं। खेतों में हरियाली, किसान कल्याण, रोजगार, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर, पेयजल परियोजनाएं, सुगम यातायात के लिए एक्सप्रेस-वे और हवाई कनेक्टिविटी सहित इस क्षेत्र के चहुंमुखी विकास का विशेष ख्याल रखा है। विशेष परियोजनाओं के नियोजन के लिए 10 करोड़ रुपये और चित्रकूट के पर्यटन विकास को नया स्वरूप देने के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। चित्रकूट के टेबल टॉप एयरपोर्ट का कार्य 70 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। इसके संचालन से रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

बुन्देलखण्ड के अन्नदाताओं को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। केन-बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह योजना बुन्देलखण्ड के लिए अमृत धारा साबित होगी।

अर्जुन सहायक परियोजना

कृषि एवं सिंचाई के लिए वरदान

उत्तर प्रदेश सरकार कृषि सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं से किसानों को लाभान्वित करा रही है। इसी क्रम में बुन्देलखण्ड की अर्जुन सहायक परियोजना किसानों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। योजना से जनपद महोबा, हमीरपुर एवं बांदा के 168 गांव के 1,49,755 किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा एवं 44,381 हेक्टेयर भूमि की सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी। इसमें महोबा जनपद की 29,680 हेक्टेयर भूमि शामिल है। साथ ही चार लाख से अधिक लोगों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह परियोजना 2,655.35 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई है। महोबा और झांसी की सीमा पर धसान नदी पर बने लहचूरा बांध से अब बरसात में बर्बाद होने वाले पानी को नवनिर्मित नहर प्रणालियों से चंद्रावल, अर्जुन व कबरई बांध से जोड़ा गया है। इस कार्य से महोबा, बांदा और हमीरपुर जनपद के किसान लाभान्वित होंगे।

1.49
लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे

44
हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी

प्रमुख विकास कार्य

- स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत झांसी में विकास कार्य
- राजकीय मेडिकल कॉलेज, झांसी में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक की स्थापना
- इण्डो-इजराइल वॉटर प्रोजेक्ट हेतु एम. ओ. यू. हस्ताक्षरित
- 4000 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं
- किसानों को बिजली बिल के फिक्स्ड चार्ज में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक की छूट
- 48.73 करोड़ रुपये की लागत से बड़वार झील को गुरसरॉय नहर से भरने हेतु फीडर कैनाल परियोजना का कार्य
- 35.6 करोड़ रुपये की लागत से विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण
- 20.11 करोड़ रुपये की लागत से गुरसरॉय में आसरा योजना के अन्तर्गत 372 आवासों का निर्माण
- 14.92 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, भरारी के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य
- 12.16 करोड़ रुपये की लागत से बिजौली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना का कार्य
- चित्रकूट में स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत परिक्रमा पथ पर कवर्ड शेड का निर्माण
- राजकीय पॉलीटेक्निक मानिकपुर का निर्माण
- कर्वी में विशिष्ट मंडी स्थल का निर्माण कार्य
- मनरेगा के अन्तर्गत मंदाकिनी नदी का पुनरोद्धार कार्य
- वाटर स्टोरेज टैंक का निर्माण
- जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत **'मेरी छत-मेरा पानी'** योजना से 28,518.72 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल आच्छादित

हिन्दुस्तान मीडिया मार्केटिंग इनीशिएटिव